CEASI MILESTONE

16th June 2025

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for Horticulture Skills in India

www.ceasi.in

हमारे बारे में

हम कौन हैं:

"सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)" एक स्वायत्त संस्था है, जो "एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)" के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्क्फोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क् का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशलयुक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- **15+ राज्य**
- **15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया**
- **20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया**
- **5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया**
- **3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया**
- **30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया**

कृषि यंत्रीकरण अभियान ने मात्र 45 दिनों में 25,000 किसानों तक पहुँच बनाई

आंध्र प्रदेश में शुरू किए गए कृषि यंत्रीकरण अभियान ने बहुत कम समय में प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की है, जहाँ केवल 45 दिनों में 25,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। यह योजना "कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM)" के अंतर्गत संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष सब्सिडी मॉडल के माध्यम से सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के तहत अब किसानों को मशीनरी खरीदते समय ही 50% की सब्सिडी मिल रही है, जिससे उन्हें अग्रिम भुगतान करने और बाद में पुनर्भुगतान के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

इस बेहतर प्रणाली ने किसानों की भागीदारी को बढ़ाया है और उन्हें भूमि तैयारी, बुवाई और कटाई जैसे कार्यों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की मशीनों तक आसान पहुंच प्रदान की है। यह पहल विशेष रूप से वर्षा आधारित और जनजातीय क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो और श्रम पर निर्भरता कम हो।

आवेदन और अनुमोदन की प्रक्रिया 'कर्षक पोर्टल – एफएम ऐप' के माध्यम से की जा रही है, जिसमें विभिन्न विभागों के डेटा को एकीकृत किया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और दोहराव से बचा जा सके। एपी एग्रोस (AP AGROS) को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो लॉजिस्टिक्स और उपकरण वितरण का समन्वय करती है।

आंध्र प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कृषि उपकरण और ड्रोन वितरित किए गए

आंध्र प्रदेश सरकार ने कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुररेड्डी पालेम (तंगुटूर मंडल) में किसानों को कृषि उपकरण, बीज और किसान ड्रोन वितरित किए। इस योजना के तहत किसानों को 80% तक की सब्सिडी सहायता दी गई।

यह पहल राज्य स्तरीय ₹100 करोड़ के निवेश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि उपकरण और तकनीक तक पहुंच दिलाकर सशक्त बनाना है। जिला स्तर पर इस योजना के तहत ₹3.98 करोड़ मूल्य के उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों की उत्पादन लागत को कम करना, कार्यकुशलता बढ़ाना और आधुनिक खेती की तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

राज्य सरकार गांव स्तर पर 800 किसान यूनियनों की स्थापना की भी योजना बना रही है। ये यूनियन किसानों को ड्रोन तक पहुंच प्रदान करेंगी और सटीक खेती (Precision Farming) को बढ़ावा देंगी, जिससे समय पर फसल प्रबंधन और उपज में सुधार संभव हो सकेगा।

वितरण कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, कृषि अधिकारी और समुदाय के सदस्य भी शामिल हुए। यह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में तकनीकी अंतर को पाटने और छोटे तथा सीमांत किसानों को आधुनिक उपकरण व ज्ञान प्रदान करने की एक

राजस्थान: किसानों के लिए कृषि उपकरण किराए पर देने हेतु 'कस्टम हायरिंग ऐप' लॉन्च

डिजिटल खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राजस्थान सरकार ने 'कस्टम हायरिंग सेंटर ऐप' लॉन्च किया है, जिसकी मदद से किसान अब अपने मोबाइल फोन से सीधे कृषि उपकरण किराए पर ले सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल जैसे जरूरी उपकरणों को मालिकाना हक के बिना उपयोग करने की सुविधा देता है।

यह ऐप विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपयोगी है, जो महंगे कृषि उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं होते। बिचौलियों को हटाकर और लॉजिस्टिक चुनौतियों को कम करके यह पहल किसानों की लागत घटाती है और उत्पादकता बढ़ाती है।

किसान ऐप के माध्यम से उपकरणों को देख सकते हैं, बुक कर सकते हैं और उन्हें अपने घर तक मंगवा सकते हैं। इसका उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस यह सुनिश्चित करता है कि दूर-दराज के इलाकों के किसान भी इस सेवा का लाभ उठा सकें।

इस ऐप के साथ-साथ राज्यभर में कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHCs) की स्थापना की गई है, जो तकनीकी सहायता और रखरखाव सेवाएं प्रदान करते हैं। ये केंद्र ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अवसंरचना भी मजबूत हो रही है।

यह पहल आधुनिक उपकरणों की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ सतत और स्मार्ट कृषि को भी बढ़ावा देती है। यह राजस्थान को कृषि में डिजिटल समाधान अपनाने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल करती है, और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ट्रैक्टर बिक्री ने मई 2025 में 9% की वृद्धि के साथ रफ्तार बनाए रखी

भारत के ट्रैक्टर बाजार ने मई 2025 में साल-दर-साल 9% की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक भावना और अनुकूल मानसून पैटर्न को दर्शाती है। ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन (TMA) के अनुसार, इस महीने कुल 90,500 ट्रैक्टरों की बिक्री हुई, जो मई 2024 में बिके 82,948 यूनिट्स की तुलना में अधिक है। ट्रैक्टर निर्यात में भी 1.3% की वृद्धि हुई, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता के संकेत मिलते हैं।

इस वृद्धि का मुख्य कारण मानसून का समय पर आना, बुवाई कार्यों की समय पर शुरुआत, और प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में सुधार को माना जा रहा है। इन कारणों से किसानों में कृषि यंत्रों की मांग में वृद्धि देखी गई है।

हालांकि निर्यात में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन देशभर में घरेलू बिक्री स्थिर रही, खासकर उन राज्यों में जहां खरीफ की तैयारी सक्रिय रूप से चल रही है। यह सकारात्मक रुझान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार और कृषि यंत्रीकरण समाधानों की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।

FARM MECHANIZATION INSIGHTS

छोटे किसानों के लिए गर्मी में राहत: एयर-कंडीशन्ड ट्रैक्टर केबिन

भारत के छोटे किसान अक्सर अत्यधिक गर्मी, धूल और बारिश जैसे कठिन मौसम में लंबे समय तक ट्रैक्टर चलाते हैं, जिससे थकान, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और उत्पादकता में कमी आती है। इस चुनौती का समाधान निकालते हुए, ट्रैक्टर डिज़ाइन में नवाचार किए जा रहे हैं ताकि ऑपरेटर की सुविधा और कार्य क्षमता में सुधार हो सके। अब छोटे ट्रैक्टरों में एयर-कंडीशन्ड केबिन लगाए जा रहे हैं, जो तापमान नियंत्रण, धूल से सुरक्षा और बारिश से बचाव प्रदान करते हैं। ये सुविधाएं विशेष रूप से उन समयों में उपयोगी हैं जब कृषि कार्य अपनी चरम अवस्था में होता है और किसान लंबे समय तक खेतों में काम करते हैं।

शुरुआत में इन केबिनों को 50 हॉर्सपावर से कम क्षमता वाले छोटे ट्रैक्टर मॉडलों के लिए विकसित किया गया था, लेकिन अब इन्हें भारत के विविध छोटे और सीमांत किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रमुख ब्रांडों के लिए भी अनुकूलित किया जा रहा है। जलवायु सहनशील यंत्रीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति यह संकेत देती है कि कृषि क्षेत्र अब किसान कल्याण और कार्यकुशलता को प्राथमिकता दे रहा है। जैसे-जैसे अधिक निर्माता इस तरह के समाधान को अपनाते जा रहे हैं, एयर-कंडीशन्ड ट्रैक्टर केबिन एक मानक सुविधा बनते जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण कृषि समुदायों के लिए बेहतर कार्य स्थितियां, अधिक उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

HORTICULTURE INSIGHTS

पडर में पीएमएफएमई योजना पर कार्यशाला आयोजित, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने पर जोर

बागवानी विभाग द्वारा पडर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PMFME) योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और नवोदित उद्यमियों को योजना के लाभ और प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना था। कार्यशाला में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जहां उन्हें वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण और बाजार से जुड़ाव जैसे विषयों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि पात्र लाभार्थियों को केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा 35% तक की सब्सिडी दी जा रही है।

प्रतिभागियों को योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया, जिसमें परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करना, उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण करना और FSSAI प्रमाणन प्राप्त करना शामिल है। कार्यशाला के दौरान भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा हुई, जिसमें जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध अवसरों पर विशेष ध्यान दिया गया। यह पहल पडर ब्लॉक में खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाती है।

चिटकुल में आधुनिक बागवानी को अपनाने की पहल

भारत सरकार के "विकसित कृषि संकल्प अभियान–2025" के अंतर्गत हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित अंतिम बसे हुए गांव चिटकुल में हाल ही में एक बागवानी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव में यह कार्यक्रम डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के किन्नौर कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) द्वारा आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्देश्य स्थानीय निवासियों को सतत फल उत्पादन के लिए आधुनिक खेती की तकनीकों से प्रशिक्षित करना था। कार्यक्रम में किसान, युवा, ग्राम पंचायत सदस्य और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

विशेषज्ञों ने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार प्राकृतिक और उच्च घनत्व वाले बागवानी मॉडल की जानकारी दी। विषयों में बाग विकास, टिकाऊ खेती के तरीके और कृषि-पर्यटन की संभावनाएं शामिल थीं। संबंधित विभागों ने किसानों के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं और तकनीकी सहायता की जानकारी दी। यह पहल स्थानीय कृषि व्यवस्था को आत्मनिर्भर, पर्यावरण अनुकूल और लचीला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

हिमाचल में अगले वर्ष से वैज्ञानिक विधि से सेब उत्पादन का आकलन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस वर्ष सेब के बॉक्सों का अनुमान जारी न करने का निर्णय लिया है, ताकि बाजार की स्थिरता प्रभावित न हो और बागवानों को किसी प्रकार की आर्थिक हानि न हो। आगामी सेब सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें अधिकारियों ने बाजार मूल्य संतुलन बनाए रखने और किसानों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सरकार ने घोषणा की है कि अगले वर्ष से सेब उत्पादन का अनुमान वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से तैयार किया जाएगा, जिससे सटीक और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हो सकें। यह कदम बागवानी क्षेत्र में बेहतर योजना, विपणन और ढांचागत प्रबंधन को बढ़ावा देगा। बैठक में सेब सीजन के दौरान आने वाली विभिन्न चुनौतियों जैसे भंडारण, परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। यह पहल राज्य में सतत और किसान केंद्रित बागवानी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन मानी जा रही है।

हरियाणा में कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ₹1267.49 करोड़ की वार्षिक योजना स्वीकृत

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत हरियाणा राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति ने वर्ष 2025–26 के लिए ₹1267.49 करोड़ की वार्षिक योजना को मंजूरी दी है। यह व्यापक वित्तीय सहायता कृषि और बागवानी क्षेत्रों में अनुसंधान, आधारभूत ढांचे और नवाचार आधारित खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी जा रही है। योजना के अंतर्गत हिसार और करनाल स्थित कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों के साथ-साथ राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें कृषि विभाग की 10, बागवानी विभाग की 2 तथा कई अनुसंधान आधारित परियोजनाएं शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, RKVY कैफेटेरिया में सम्मिलित योजनाओं के तहत भी कई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें SMAM, CRM, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, फसल विविधिकरण, परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) और "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" जैसी पहलें शामिल हैं। विशेष रूप से "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" के तहत ₹41598.04 लाख की राशि सूक्ष्म सिंचाई और भूमिगत पाइपलाइन जैसी जल-संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत की गई है। इन पहलों का उद्देश्य जल संरक्षण, ऊर्जा और श्रम की बचत, खेती योग्य भूमि का विस्तार और सतत कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना है।

आंध्र प्रदेश सरकार बागवानी किसानों को राहत देने के लिए उठाएगी ठोस कदम

आंध्र प्रदेश सरकार ने तंबाकू, आम और कोको जैसी प्रमुख फसलों की खरीद और मूल्य निर्धारण से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई रणनीतिक पहल की हैं। किसान-केन्द्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को क्षेत्रीय भ्रमण कर समस्याओं की पहचान करने और उत्पादन में वैश्विक मानकों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोको की गुणवत्ता बढ़ाने और किसानों में जागरूकता लाने के लिए एक समर्पित नीति लाई जाएगी। साथ ही, कृषक उत्पादक संगठन (FPO) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को प्रसंस्करण क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु सहायता दी जाएगी।

तंबाकू क्षेत्र में, फ्लू-क्योरड वर्जीनिया (FCV) खेती को नियंत्रित किया जाएगा जबकि व्हाइट बर्ले तंबाकू अनुबंध खेती के माध्यम से उत्पादित होगी। सात प्रमुख मंडियों से 2.5 करोड़ किलोग्राम तंबाकू की खरीद की जाएगी। आम के क्षेत्र में कम मांग के चलते सरकार किसानों को ₹8 प्रति किलोग्राम की दर पर खरीद होने की स्थिति में ₹4 प्रति किलोग्राम का मुआवजा देगी। कोको के लिए ₹500 न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने हेतु ₹50 की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही, 116 से बढ़ाकर 200 रैतु बाजारों की स्थापना, मोबाइल मार्केट और पीएम-किसान से जुड़ा किसान डेटाबेस विकसित किया जाएगा।

दूध उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए 'सांची रथ' की शुरुआत

दूध और दुग्ध उत्पादों की शुद्धता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भोपाल सहकारी दुग्ध संघ ने "दूध का दूध – पानी का पानी" अभियान के तहत एक मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला अभियान "सांची रथ" की शुरुआत की है। यह अत्याधुनिक मोबाइल लैब भोपाल की विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में जाकर दूध, दही, पनीर, घी आदि के मौके पर ही परीक्षण कर रही है। जांच के परिणाम उपभोक्ताओं को तुरंत व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है।

यह अभियान 7 जून 2025 को फॉर्च्यून सिग्नेचर सोसाइटी और इंडस गार्डन सोसाइटी से शुरू हुआ, जहां 44 नमूनों की जांच की गई—जिनमें से 12 नमूने मिलावटी पाए गए (5 में स्टार्च और 7 में पानी की मिलावट)। 14 जून को मीनाल रेजीडेंसी में 42 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 24 नमूने मिलावटी थे (20 में पानी और 4 में स्टार्च की मिलावट थी)।

भोपाल दुग्ध संघ के सीईओ प्रीतेश जोशी ने मिलावट, खासकर दूषित पानी से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चेतावनी दी और उपभोक्ताओं से ब्रांडेड, भरोसेमंद दुग्ध उत्पादों का उपयोग करने की अपील की। परीक्षण के साथ-साथ, जागरूकता सत्र और पर्चों के माध्यम से निवासियों को मिलावट पहचानने और संदिग्ध उत्पादों की रिपोर्ट करने के तरीके सिखाए जा रहे हैं।

यह पहल उपभोक्ताओं में विश्वास बढ़ाने, अनैतिक गतिविधियों को रोकने और जनस्वास्थ्य की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है — जो "सांची" ब्रांड की विश्वसनीयता को और मजबूत करता है।

फ्राइज़वाल: भारत के लिए उच्च दुग्ध उत्पादन और जलवायु-अनुकूल डेयरी नस्ल

फ्राइज़वाल एक सिंथेटिक डेयरी गाय की नस्ल है, जिसे ICAR-CIRC, मेरठ और मिलिट्री फार्म्स द्वारा विकसित किया गया है। यह नस्ल होल्स्टीन फ्राइज़ियन (62.5%) और साहीवाल (37.5%) के आनुवंशिक संयोजन से बनाई गई है। इसे 300 दिनों की दुग्ध अवधि में 4,000 किलोग्राम दूध और 4% वसा उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका पंजीकरण संख्या INDIA_CATTLESYNTHETIC_2024_FRIESWAL_04001 है, और यह भारत की सबसे सफल क्रॉसब्रीड नस्लों में से एक मानी जाती है।

1987 में मेरठ स्थित मिलिट्री फार्म स्कूल से शुरू हुए इस परियोजना का विस्तार 37 मिलिट्री फार्म्स तक किया गया। इस नस्ल के विकास में इंटर से मेटिंग, प्रोजेनी टेस्टिंग और जेनेटिक सिलेक्शन की कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे बेहतर प्रदर्शन और अनुकूलता सुनिश्चित होती है। मेरठ, अंबाला, जालंधर, लखनऊ, बरेली और देहरादून स्थित डेटा रिकॉर्डिंग केंद्र दूध उत्पादन, वसा प्रतिशत और प्रजनन क्षमता की निगरानी करते हैं।

मूलतः रक्षा बलों की आवश्यकताओं के लिए बनाए गए मिलिट्री फार्म्स ने यूरोपीय और भारतीय नस्लों के संयोजन से फ्राइज़वाल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1991-92 में मिलिट्री फार्म्स ने 2,833 मिलियन लीटर दूध का उत्पादन किया, जिसमें फ्राइज़वाल ने लागत-कुशल विकल्प के रूप में अपनी उपयोगिता सिद्ध की।

आज फ्राइज़वाल भारत के डेयरी क्षेत्र की रीढ़ बनती जा रही है—जो किसानों की आय, दूध की आपूर्ति, और सतत डेयरी विकास में योगदान दे रही है। निरंतर अनुसंधान और क्षेत्रीय क्रियान्वयन के साथ, इसका लक्ष्य भारत की पहली राष्ट्रीय स्तर की उच्च-दूध उत्पादन नस्ल बनना है।

जेपीएमएफ ने लॉन्च किया 'मेधा रागी लड्डू' – झारखंड से एक सेहतमंद मिठाई

झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड (जेपीएमएफ), जो कि एनडीडीबी द्वारा संचालित है, ने 6 जून 2025 को रांची में मेधा मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला समारोह के दौरान अपनी नई पोषणयुक्त मिठाई "मेधा रागी लड्डू" को लॉन्च किया। इस उत्पाद का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और एनडीडीबी अध्यक्ष डॉ. मीनेश सी. शाह द्वारा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया।

"मेधा रागी लड्डू" एक स्वास्थ्यवर्धक मिठाई है, जिसे रागी (मडुआ), गुड़, शुद्ध मेधा घी और भुने हुए मूंगफली व तिल से तैयार किया गया है। झारखंड में प्रचुर मात्रा में उगने वाला रागी कैल्शियम, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है तथा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। वहीं गुड़ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पाचन में मदद करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है और श्वसन तथा त्वचा स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।

इन लड्डुओं को पारंपरिक सूखी भूनने की विधि से तैयार किया जाता है ताकि पोषण बरकरार रहे। फिर इन्हें MAP पैकेजिंग के ज़रिए स्वच्छता के साथ पैक किया जाता है ताकि ताजगी बनी रहे। जेपीएमएफ की प्रोडक्शन और क्वालिटी टीम द्वारा कई परीक्षणों के बाद विकसित यह उत्पाद स्वाद, स्वास्थ्य और बजट – तीनों का सही संतुलन प्रस्तुत करता है, और इसे 200 ग्राम के पैक में उपलब्ध किया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने 'कामधेनु निवास' आत्मनिर्भर गोशालाओं के लिए नीति को दी मंजूरी

मध्य प्रदेश सरकार ने "आत्मनिर्भर गोशालाओं की स्थापना हेतु नीति (कामधेनु निवास), 2025" को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य आवारा गौवंश की देखभाल के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान करना है। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की, जिसमें राज्य भर में बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर गोशालाओं की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

प्रत्येक कामधेनु निवास में कम से कम 5,000 गौवंश रखे जाएंगे, जिनमें से 30% तक उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्लें हो सकती हैं। इन गोशालाओं को समर्थन देने के लिए सरकार प्रत्येक इकाई को अधिकतम 125 एकड़ शासकीय भूमि आवंटित करेगी। यदि गोशाला में 5,000 से अधिक मवेशी होंगे, तो प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 मवेशियों पर 25 एकड़ अतिरिक्त भूमि दी जाएगी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग एक भूमि बैंक तैयार करेगा और भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। संचालन करने वाली संस्था और मध्य प्रदेश गौ संरक्षण बोर्ड के बीच एक उपयोग समझौता किया जाएगा।

पंजीकृत फर्म, ट्रस्ट, सोसायटी, कंपनियाँ या अधिकतम पाँच संस्थाओं के संघ इन गोशालाओं को संचालित करने के लिए पात्र होंगे। पाँच से अधिक संस्थाओं वाले संघों को इस योजना के अंतर्गत मान्यता नहीं मिलेगी।

गौसेवा के साथ-साथ ये गोशालाएँ पंचगव्य उत्पाद निर्माण, बायोगैस उत्पादन, जैविक खाद निर्माण, नस्ल सुधार, डेयरी प्रसंस्करण, और सौर ऊर्जा जैसे सतत एवं आत्मनिर्भर गतिविधियों में भी शामिल होंगी, जिससे राज्य के पशुधन क्षेत्र में स्थायी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

DAIRY INSIGHTS

एमपीसीडीएफ ने ईआरपी और मोबाइल ऐप एकीकरण के साथ अपनाया डिजिटल परिवर्तन

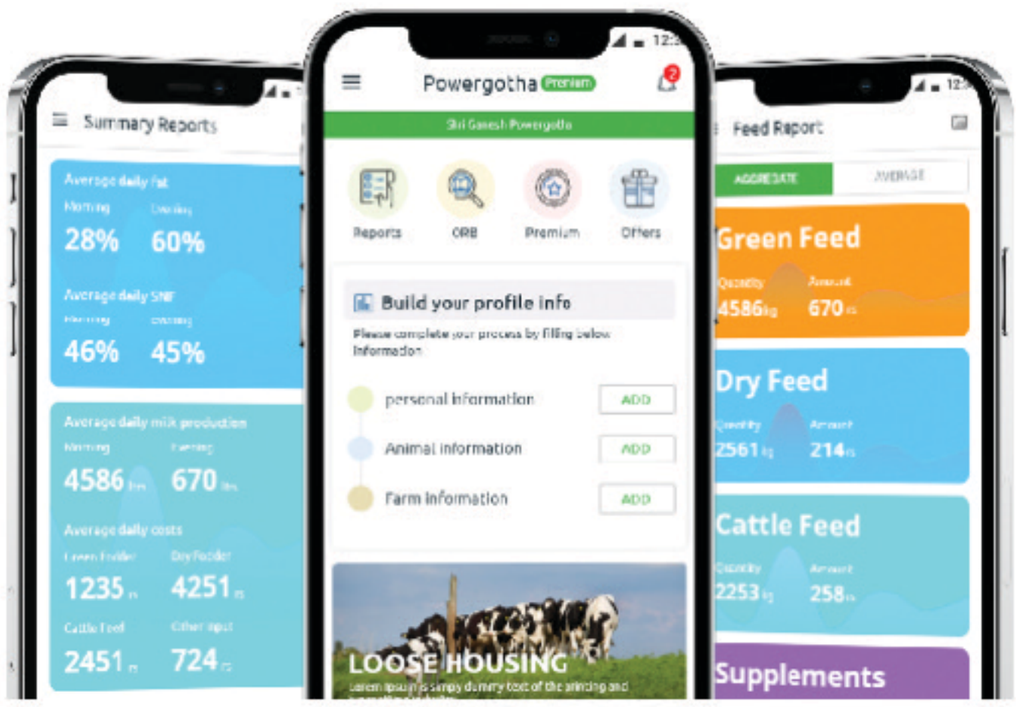

मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (MPCDF) ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण डिजिटल परिवर्तन की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता और संचालन क्षमता को बढ़ाना है। इसके तहत MPCDF ने अपने मुख्य कार्यों को डिजिटाइज़ करने के लिए एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ERP) सिस्टम लागू किया है, जिससे ये प्रक्रियाएँ अब ऑनलाइन सुलभ और प्रबंधनीय हो गई हैं।

एक प्रमुख कदम के रूप में, MPCDF ने NDDB के सहयोग से मोबाइल ऐप-आधारित दूध संग्रहण प्रणाली शुरू की है। यह ऐप ERP प्लेटफॉर्म से सीधे जुड़ा है, जिससे किसानों को उचित मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है। यह एकीकृत प्रणाली भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाती है, पारदर्शिता बढ़ाती है, और दूध संग्रहण प्रणाली की लागत को कम करती है।

यह डिजिटल पहल इंदौर डेयरी फेडरेशन के सीईओ द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च की गई, जिससे मध्य प्रदेश के डेयरी क्षेत्र में तकनीक आधारित परिवर्तन की शुरुआत हुई।

डॉ. संजय गोवानी, प्रबंध निदेशक, MPCDF ने कहा कि यह पहल किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इसे जल्द ही राज्य की अन्य डेयरी फेडरेशनों में भी लागू किया जाएगा। यह डिजिटलीकरण किसानों की आय बढ़ाने, दूध संग्रहण को अधिक प्रभावी बनाने और डेयरी संचालन को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा।

GENERAL AGRICULTURE INSIGHTS

भारत में कृषि उत्पादन में 10 वर्षों में 40% की वृद्धि

भारत के कृषि क्षेत्र ने पिछले 10 वर्षों में 40% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जिससे खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिली है। वित्त वर्ष 2024–25 की चौथी तिमाही में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.4% रही, जो वैश्विक मानकों की तुलना में काफी अधिक है, जहां 1–2% वृद्धि को भी बड़ी उपलब्धि माना जाता है। यह प्रगति नीतिगत पहलों, बेहतर कृषि तकनीकों और किसानों को निरंतर समर्थन देने के कारण संभव हुई है। गेहूं, धान, सोयाबीन और मूंगफली जैसे प्रमुख फसलों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है और देश के अनाज भंडार पूरी तरह भरे हुए हैं।

इस तेज़ विकास के चलते भारत न केवल अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि अन्य देशों को निर्यात भी कर रहा है। यह उपलब्धि अनुसंधान, किसान सशक्तिकरण और कृषि अवसंरचना के विकास की दिशा में किए गए सतत प्रयासों का परिणाम है। यह प्रगति एक विकसित और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भारत में पुनर्योजी कृषि को मिला बढ़ावा: जलवायु-लचीली और टिकाऊ खेती की दिशा में बड़ा कदम

क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड अवॉर्ड्स (CASCA'25) के दौरान, सीएसआर, विकास और जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़े विशेषज्ञों ने दीर्घकालिक, समुदाय-आधारित रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि कृषि को जलवायु के प्रति लचीला और टिकाऊ बनाया जा सके। वक्ताओं ने अल्पकालिक परियोजना-आधारित हस्तक्षेपों के बजाय स्थानीय स्वामित्व को प्राथमिकता देने वाले सशक्तिकरण मॉडल को अपनाने की बात कही। पुनर्योजी कृषि के अंतर्गत जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और उन्नत कृषि तकनीकों जैसी विधियों पर चर्चा हुई, जो स्थानीय चुनौतियों के अनुसार अनुकूलित की जा सकती हैं।

परिचर्चा में ऐसे उदाहरण सामने आए जहाँ जल संग्रहण, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि तकनीकों का पुनः उपयोग और सामुदायिक भागीदारी से आय और कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों ने पर्यावरण-संवेदनशील सीएसआर रणनीतियों के माध्यम से स्थायी बदलाव लाने में निजी क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित किया। पुनर्योजी कृषि को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक भागीदारी का संगम मानते हुए, विशेषज्ञों ने इसे भारत की कृषि को टिकाऊ और जलवायु-सुरक्षित बनाने के लिए एक व्यावहारिक और व्यापक समाधान बताया।

कॉरपोरेट्स ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एफपीओ से सीधी खरीद शुरू की

किसानों की आय बढ़ाने और कृषि व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम उठाते हुए, बड़ी कंपनियों ने किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) से सीधी फसल खरीद शुरू कर दी है। यह पहल सरकार द्वारा आयोजित साप्ताहिक वेबिनार के बाद शुरू हुई, जिनका उद्देश्य एफपीओ को कॉरपोरेट खरीदारों से जोड़ना था। कई एफपीओ पहले यह नहीं जानते थे कि वे कंपनियों को सीधे बेच सकते हैं।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस बदलाव के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। एफपीओ ने गेहूं और मक्का जैसी फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त किए हैं क्योंकि उन्होंने सीधे बिक्री की, जिससे बिचौलियों का खर्च बचा। सरकार अब एफपीओ के लिए मंडी शुल्क समाप्त करने पर भी विचार कर रही है ताकि उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े।

ओलम इंडिया ने उत्तर प्रदेश और बिहार के एफपीओ से 800 टन मक्का और 3,000 टन गेहूं खरीदे हैं। ब्रिटानिया, मदर डेयरी और एचआईएल जैसी अन्य बड़ी कंपनियां भी इस मॉडल से जुड़ रही हैं।

कृषि मंत्रालय, सचिव देवेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में, पिछले दो महीनों से वेबिनार आयोजित कर रहा है, जिससे एफपीओ को कंपनियों से सीधा संवाद करने का अवसर मिल रहा है।

साथ ही, सरकार एफपीओ को ओएनडीसी (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्यक्ष उपभोक्ता बिक्री के लिए प्रोत्साहित कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एफपीओ उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखें, तो वे 5–6% तक अधिक लाभ कमा सकते हैं।

अब जबकि 10,000 एफपीओ स्थापित हो चुके हैं, सरकार का ध्यान उनकी बाजार से कनेक्टिविटी और मुनाफे में वृद्धि पर केंद्रित है।

ICRISAT के वैज्ञानिकों ने विकसित की 45°C तापमान सहने वाली कम अवधि वाली अरहर की किस्म

एक प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अरहर (तुअर) की एक नई किस्म ICPV 25444 विकसित की है, जो अत्यधिक गर्मी—अर्थात 45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान—को सहन कर सकती है और मात्र 125 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म का सफलतापूर्वक परीक्षण कर्नाटक, ओडिशा और तेलंगाना में किया गया है, जहां यह प्रति हेक्टेयर 2 टन तक उत्पादन देती है।

जहाँ पहले अरहर को केवल खरीफ मौसम की फसल माना जाता था, वहीं अब यह किस्म फोटो और तापमान असंवेदनशील होने के कारण साल भर उगाई जा सकती है। यह नवाचार नाड़ी (दाल) उत्पादन में कमी को दूर करने और जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

इस सफलता को स्पीड-ब्रीडिंग प्रोटोकॉल के ज़रिए हासिल किया गया है, जिससे एक साल में चार पीढ़ियाँ (generations) तैयार की जा सकती हैं और एक नई किस्म विकसित करने में लगने वाला समय 15 वर्षों से घटकर केवल 5 वर्ष रह गया है। इस प्रक्रिया में जीनोमिक टूल्स और नियंत्रित वातावरण में घनत्वयुक्त बुवाई का प्रयोग किया गया।

भारत में वर्तमान में लगभग 35 लाख टन अरहर का उत्पादन होता है, जबकि मांग इससे 15 लाख टन अधिक है। इस अंतर को पूरा करने के लिए देश को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। नई किस्म की उच्च उत्पादकता (1.5–2 टन/हेक्टेयर) इसे लाभकारी बनाती है और यह धान की परती भूमि तथा कमांड क्षेत्रों के अंतिम हिस्सों में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है।

कर्नाटक के बागलकोट में गर्मियों की चरम परिस्थितियों में भी स्थानीय परीक्षणों में इस किस्म ने अच्छे परिणाम दिखाए हैं। इसकी जलवायु के अनुसार अनुकूलन क्षमता इसे भारत के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में फैलाने के लिए उपयुक्त बनाती है, जिससे किसानों को एक विश्वसनीय दाल फसल विकल्प उपलब्ध होगा।

राष्ट्रीय विचार-मंथन सत्र में गन्ने की जलवायु-सहनशील किस्मों की तात्कालिक आवश्यकता पर बल

नई दिल्ली में गन्ने के टिकाऊ उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्तर का ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र आयोजित किया गया। कृषि एवं खाद्य विभाग से जुड़े प्रमुख हितधारकों द्वारा आयोजित इस सत्र में गन्ने की घटती पैदावार, कीट प्रकोप, जलवायु अनिश्चितताएं और खेती के घटते क्षेत्र जैसी चुनौतियों पर चर्चा की गई।

सत्र में एक छह बिंदुओं वाली कार्य योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें किस्मों में विविधता लाना, जीनोम इनोवेशन, विकेन्द्रीकृत बीज प्रणाली, जलवायु-समर्थनशील कृषि पद्धतियां और नीतिगत सुधार शामिल थे। एक महत्वपूर्ण सुझाव

GENERAL AGRICULTURE INSIGHTS

'राष्ट्रीय गन्ना मिशन' की शुरुआत करने का था, जिससे सरकार, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के प्रयासों का समन्वय हो सके।

वरिष्ठ अधिकारियों ने गन्ने की फसल को भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया, जो 5.5 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करती है और किसानों को हर वर्ष भारी भुगतान सुनिश्चित करती है। चर्चा में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि स्थान-विशेष की जलवायु और रोग सहनशील गन्ना किस्मों का विकास किया जाए ताकि पैदावार में स्थिरता आ सके और लाभ बढ़े।

प्रतिभागियों ने बेहतर मशीनीकरण, डिजिटल उपकरणों, किसान प्रशिक्षण, और रियल-टाइम डाटा के उपयोग पर भी विचार किया जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहतर हो सके। सत्र का समापन इस अपील के साथ हुआ कि गन्ना क्षेत्र को नवाचार और सहयोग के माध्यम से पुनर्जीवित करने हेतु समयबद्ध और उत्तरदायी कार्रवाई की जाए।

CEASI ACTIVITIES

PROMOTING SUSTAINABLE SUGARCANE CULTIVATION IN AYODHYA

Under the Sashwat Mithas project, the Centers of Excellence for Agriculture Skills in India, in collaborationwith UPL SAS Limited, is implementing sustainable sugarcane cultivation practices in Ayodhya. The projectfocuses on enhancing farmers' knowledge and skills related to eco-friendly farming techniques. A dedicated team is actively conducting field surveys to assess current farming practices and identify areasfor improvement. Additionally, the establishment of demonstration plots is underway at the field level,showcasing sustainable methods of sugarcane cultivation.These demo plots serve as practical examples to guide farmers in adopting better practices, which includewater management, soil health improvement, and the use of organic fertilizers. Through these efforts, theproject aims to create awareness among local farmers about the importance of sustainable agriculture forboth improved yields and environmental conservation.

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

(CEASI), Unit No. 101, First Floor, Greenwoods Plaza, Block 'B' Greenwoods City, Sector-45, Gurugram, Haryana-122009

+91 74287 06078

info@cedsi.in

www.ceasi.in

@ceasi_india